नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 027
दि. 27.05.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सीएम योगी ने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पीएम नरेन्द्र मोदी को अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे करने पर दी बधाई

सेवा, सुशासन और लोक-कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई!

(जीएनएस)।

लखनऊः देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 26 मई का विशेष महत्व है, क्योंकि 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेन्द्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी। नरेन्द्र मोदी ने 2019 में लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और इस बार भी 26 मई की तारीख का एक खास महत्व था। दरअसल 26 मई 2019 को ही राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को मोदी को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस पद पर अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'प्रधान सेवक'के रूप में सेवा, सुशासन और लोक-कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई! 'विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 'प्रधान सेवक' के रूप में सेवा, सुशासन और लोक-कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई!

इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जनभागीदारी ने विकास को जन-आंदोलन का रूप दिया। यही वह दृष्टि है, जिसने ऐसे 'नए भारत' को गढ़ा, जहां नारी सशक्तीकरण, नवाचार, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं।

सीमाओं पर अडिग, आतंक के विरुद्ध निर्णायक और विश्व मंच पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत आज एक सशक्त, विश्वसनीय नेतृत्व के रूप में स्थापित है। डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी 'विकसित भारत 2047' की दिशा में नई गति दे रही है।

प्रधानमंत्री आवास, जन-धन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और स्वनिधि जैसी योजनाओं ने विकास को जन-जीवन तक पहुंचाकर विश्वास को सशक्त किया है और यही विश्वास 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' को साकार कर रहा है। 'नेशन फर्स्ट' की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ती इस युगांतकारी यात्रा के लिए प्रधानमंत्री जी का कोटि-कोटि अभिनंदन।

प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल में भारत का आत्मविश्वास लौटा : नवीन

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के मंगलवार को 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 26 मई 2014 को शुरू हुआ दौर केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि देश के आत्मविश्वास की वापसी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण है।

नवीन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स'पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'के मंत्र तथा 'अंत्योदय'के सिद्धांत से प्रेरित मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नीतियां कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में बदलाव का माध्यम बनें।

उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को "संकल्प से सिद्धि के 12 गौरवशाली वर्ष"बताया।

नवीन ने कहा, "जहां एक ओर जनधन, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) और डिजिटल क्रांति से अंतिम छोर पर बैठे गरीब का सशक्तीकरण हुआ, वहीं 'विकास भी, विरासत भी'के संकल्प से आधुनिक अवसंरचना के साथ देश के सांस्कृतिक गौरव का पुनरुद्धार हुआ है।"

शिवराज की नई पुस्तक 'अपनापनः नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अनुभव' का विमोचन, सुनाया ईमेल-फीमेल वाला किस्सा

नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक के विमोचन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक पुराना किस्सा साझा किया। शिवराज सिंह ने 'अपनापनः नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अनुभव' नाम की नई किताब लिखी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपनी नई पुस्तक 'अपनापनः नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अनुभव' का विमोचन किया। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता पारंपरिक तरीके से काम करते रहे हैं और कई बार तकनीक का व्यापक उपयोग करने की मानसिकता नहीं रही। उन्होंने मोबाइल फोन के शुरूआती दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय इसे 'फाइव-स्टार कल्चर' से जोड़ा जाता था। विमोचन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि जब नरेंद्र मोदी पार्टी के प्रभारी के तौर पर मध्य प्रदेश आए थे, तब मैं राज्य इकाई में महासचिव था। इस दौरान चुनाव तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई थी। शिवराज सिंह ने कहा, "बैठक के दौरान जब पीएम मोदी ने पूछा कि किसके पास ईमेल आईडी है, तो उस समय शायद ही किसी के पास इसका जवाब था। लोग एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने मजाक में पूछा, "नरेंद्र भाई, आप यह 'फीमेल-फीमेल' क्या कह रहे हैं? इस फीमेल-ईमेल से क्या होगा?"

कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ किया अभद्र भाषा का प्रयोग, बोले- बांग्लादेश से कहो डीजल चाहिए तो प्याज खरीदो

महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब कर दिए और उन्होंने हमारा प्याज खरीदना बंद कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों प्याज की खेती करने वाले किसान भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि किसानों से मंडी में एक रुपये प्रति किलो प्याज थोक भाव में खरीदी जा रही है, जबकि बाजार में प्याज की फुटकर कीमत 20 से 25 रुपये किलो है।

इसे लेकर किसान नाराज है और अपनी फसलें सड़कों पर फेंक कर रोष व्यक्त कर रहे हैं।

दिल्ली में अब ₹2.5 लाख सालाना कमाई वाले भी बना सकेंगे राशन कार्ड, कैसे करें आवेदन

(जीएनएस)।

दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। लंबे इंतजार के बाद राजधानी में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना आय सीमा बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने की तैयारी है। इससे लाखों ऐसे परिवारों को राहत मिलने वाली है, जो अब तक राशन सुविधा से बाहर थे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए बड़ा कदम बताया है। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल और पारदर्शी होगी ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाकर सही लोगों तक राशन पहुंचाया जा सके।

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

आवेदन सीधे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा। सरकार ने 15 मई 2026 से नए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। पुराने लंबित आवेदनों को भी दोबारा अपडेट करने का मौका दिया गया है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था, वे अब नई आय सीमा और नए दस्तावेजों के साथ दोबारा फॉर्म जमा कर सकते हैं।

₹1 लाख से सीधे ₹2.5 लाख तक पहुंची सीमा

पहले राशन कार्ड के लिए सालाना पारिवारिक आय सीमा केवल ₹1 लाख थी। बाद में इसे बढ़ाकर ₹1.20 लाख किया गया। अब सरकार इसे बढ़ाकर ₹2.5 लाख तक ले जाने की तैयारी में है।

यूपी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म, सभी ग्राम प्रधान अब बनेंगे प्रशासक, पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है. अब सभी निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाया जाएगा. नई पंचायतों के गठन या अधिकतम छह महीने तक प्रधान प्रशासनिक काम संभालेंगे. सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए नया आयोग भी गठन पहले ही कर दिया है.

उत्तर प्रदेश के गांवों में अब सत्ता की तस्वीर बदलने वाली है. पंचायतों का कार्यकाल खत्म होते ही हजारों ग्राम प्रधान कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि नए अधिकार के साथ फिर उसी कुर्सी पर बैठेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि नई पंचायतों के गठन तक पुराने प्रधान ही गांवों के प्रशासक बनकर काम संभालेंगे. पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण के बीच आए इस फैसले ने गांव की राजनीति में हलचल तेज कर दी है. अब हर चौपाल पर चर्चा इसी बात की है कि आखिर योगी सरकार ने चुनाव से पहले इतना बड़ा दांव क्यों चला.

प्रदेश की ग्राम पंचायतों का वर्तमान कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि नई पंचायतों के गठन तक गांवों का कामकाज कौन संभालेगा. अब सरकार ने इसका जवाब दे दिया है. सरकारी आदेश के मुताबिक 27 मई 2026 से सभी निवर्तमान ग्राम प्रधान अपने-अपने गांव में प्रशासक के रूप में काम करेंगे. यह व्यवस्था नई पंचायतों के गठन तक या अधिकतम छह महीने तक लागू रहेगी. सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत कर दिया है. यानी हर जिले में डीएम निवर्तमान प्रधानों को औपचारिक रूप से प्रशासक नामित करेंगे.

यूपी में पंचायत चुनाव के लिए डइउ का कोटा तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है.

हालांकि सरकार ने इस व्यवस्था के साथ कुछ सख्त शर्तें भी जोड़ दी हैं. प्रशासक बनाए गए प्रधान सिर्फ सामान्य और रूटीन प्रशासनिक काम ही कर सकेंगे. उन्हें कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेने की अनुमति नहीं होगी. यानी गांव में रोजमर्रा के काम सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, छोटी प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की सामान्य निगरानी जैसे कार्य जारी रहेंगे, लेकिन नई योजना या बड़े वित्तीय फैसले नहीं लिए जा सकेंगे. विशेष परिस्थिति में डीएम की अनुमति जरूरी

सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी गांव में कोई विशेष स्थिति बनती है और बड़ा निर्णय लेना जरूरी होता है, तो प्रधान सीधे फैसला नहीं ले सकेंगे. ऐसे मामलों में प्रस्ताव पहले जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के पास भेजा जाएगा. डीएम की मंजूरी के बाद ही कोई निर्णय लागू हो सकेगा. सरकार का कहना है कि इसका मकसद प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना और चुनाव से पहले किसी तरह के विवाद से बचना है. सरकार के इस फैसले के बाद गांवों में राजनीतिक चचाएं भी तेज हो गई हैं. कई प्रधान इसे राहत भरा फैसला मान रहे हैं क्योंकि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उनका प्रभाव बना रहेगा. वहीं विपक्षी दल इसे पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक संतुलन साधने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में इस फैसले का असर इसलिए भी ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि ग्राम प्रधान गांव की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक इकाई माने जाते हैं.

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ईसीआई ने किया ऐलान, कौन हैं ये 7 खाली सीटें जिनके लिए होगी वोटिंग?

(जीएनएस)।

भारतीय निर्वाचन आयोग (एउक) ने कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये मतदान 18 जून 2026 को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होंगे, जबकि मतगणना उसी दिन शाम 5:00 बजे शुरू की जाएगी। यह चुनाव राज्य की विधान परिषद की सात सीटों को भरने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख क्या है?

निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की गई है। इसके बाद 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 जून 2026 तक संपन्न कर ली जाएगी।

कर्नाटक में किन दिग्गज नेताओं की सीट हो रही खाली?

यह चुनाव उन सात सीटों को भरने के लिए हो रहे हैं, जिनके मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 30 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में गोविंद राजू, नजीर अहमद, एन. नागराजू (एमटीबी), प्रताप सिंहा नायक के, तिप्पन्नप्पा, सुनील वल्यापुर और बी.के. हरिप्रसाद शामिल हैं। इन सदस्यों के सेवानिवृत्त होने से विधान परिषद की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा।

क्यों जरूरी है ये चुनाव?

कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य विधायकों (MLAs) द्वारा चुने जाते हैं और ये ऊपरी सदन में कानूनों की समीक्षा और नीतिगत चर्चा में अहम भूमिका निभाते हैं। यह चुनाव न केवल राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करेगा, बल्कि विभिन्न दलों की शक्ति स्थिति पर भी असर डालेगा।

कांग्रेस के नए सीएम वी डी सतीशन पीएम मोदी से मिलने पहुंचे, सौंप दी डिमांड की लिस्ट

केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने मंगलवार (26 मई 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच केरल से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर साझा की. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर केरल से जुड़े अलग-अलग मामलों पर चर्चा की. वी. डी. सतीशन ने कहा कि राज्य के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से हर तरह की मदद और सहयोग देने का अनुरोध किया गया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से केरल के विकास कार्यों और राज्य की जरूरतों को लेकर समर्थन मांगा।

क्वाड देशों ने इंडो-पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने और चीन की बढ़ती चुनौती के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का दिया संकेत

(जीएनएस)।

भारत की मेजबानी में दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री निगरानी, सप्लाई चेन और नई टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री शामिल हुए।

बैठक में होर्मुज स्ट्रेट संकट, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों की आजादी पर भी खास फोकस रहा। क्वाड देशों ने इंडो-पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने और चीन की बढ़ती चुनौती के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का संकेत दिया।

क्वाड बैठक में सबसे ज्यादा जोर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चारों देश समुद्री लोकतंत्र हैं और इस इलाके में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। बैठक में समुद्री निगरानी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडरसी केबल सुरक्षा और आपदा राहत जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की बात हुई। क्वाड देशों ने साफ किया कि इंडो-पैसिफिक को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए मिलकर काम जारी रहेगा।

होर्मुज संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि ईरान अगर होर्मुज स्ट्रेट को बंद करता है तो इसका बड़ा असर इंडो-पैसिफिक देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समुद्री रास्तों की आजादी बनाए रखना बेहद जरूरी है।

वोंग ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की डिप्लोमैटिक कोशिशों की तारीफ की और कहा कि क्वाड देशों की जिम्मेदारी है कि वे इलाके में स्थिरता और भरोसेमंद विकल्प तैयार करें।

अमेरिका की दो बड़ी समुद्री पहल

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बैठक के बाद समुद्री सुरक्षा से जुड़ी दो बड़ी घोषणाएं कीं। पहली, इंडो-पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग पहल, जिसके जरिए क्वाड देश समुद्री सूचनाओं को साझा करेंगे।

सेंटर की क्षमता 399, एडमिट कार्ड बांटे 819! रद्द हुई परीक्षा, कब होगा अब एग्जाम?

(जीएनएस)।

कानपुर, एसएससी जीडी परीक्षा देने पहुंचे सैकड़ों छात्रों के लिए सोमवार का दिन परेशानी भरा साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक परीक्षा केंद्र पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब परीक्षा देने पहुंचे छात्रों की संख्या केंद्र की क्षमता से लगभग दोगुनी निकली। कई उम्मीदवार घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल पाया।

स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने पड़े। बाद में छात्रों और आयोग के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। इस घटना के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी भी देखने को मिली, क्योंकि वे दूर-दूर से परीक्षा देने पहुंचे थे। अब आयोग की ओर से नई परीक्षा तिथि जल्द जारी किए जाने की बात कही गई है।

क्षमता से दोगुने एडमिट कार्ड जारी

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को कानपुर के पुरवामीर स्थित श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन सेंटर में एसएससी जीडी परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। केंद्र की कुल सीट क्षमता 399 थी, लेकिन दूसरी शिफ्ट के लिए करीब 819 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए।

अधिकारियों को करना पड़ा हस्तक्षेप

स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।

काफी देर तक छात्रों से बातचीत चली। उम्मीदवारों ने कहा कि गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उन्हें आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी किया गया था।

बाद में अधिकारियों ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। छात्रों को भरोसा दिया गया कि जल्द ही नई परीक्षा तिथि जारी की जाएगी। आयोग की ओर से कहा गया कि नई जानकारी आधिकारिक वेबसाइट और ईमेल के जरिए उम्मीदवारों तक पहुंचाई जाएगी।

हर साल होती है SSC GD भर्ती परीक्षा

एसएससी जीडी परीक्षा हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जाती है। इसके जरिए देश की अलग-अलग अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा संगठनों में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती की जाती है।

इस परीक्षा में देशभर से लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) समेत कई केंद्रीय सुरक्षा बलों में की जाती है।

इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 25,487 पद भरे जाने हैं। इनमें BSF में 616 पद, CISF में 14,595 पद, CRPF में 5,490 पद, SSB में 1,764 पद, ITBP में 1,293 पद, असम राइफल्स में 1,706 पद और SSF में 23 पद शामिल हैं।

'पेशेवर अपराधी-माफियाओं को जेल में ही रखें': सीएम योगी, छोटे अपराधों में ओपन जेल मॉडल अपनाने के दिए निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार, जवाबदेही और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अलग-अलग विभागों की समीक्षा बैठकों में कई अहम निर्देश दिए। जेल विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि जेलों को सिर्फ बंदियों को रखने का स्थान न मानकर सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही छोटे अपराधों में 'ओपन जेल'की अवधारणा को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। वहीं, राज्य कर विभाग की समीक्षा में टैक्स प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। कृषि विभाग की समीक्षा में खरीफ सीजन की तैयारियां समय से पूरी करने, सूखा प्रभावित इलाकों के लिए रणनीति बनाने और किसानों तक तकनीकी सलाह पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

जेल सिर्फ पेशेवर अपराधियों और माफिया के लिए हों

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेलों को केवल कैदियों को रखने का केंद्र न मानकर उन्हें सुधार और पुनर्वास की दिशा में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेशेवर अपराधियों और माफिया के लिए जेल जरूरी हैं, लेकिन छोटे अपराधों में 'ओपन जेल'की अवधारणा अधिक उपयोगी हो सकती है। इसके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि सभी जेलों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, तकनीकी सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं और बेहतर की जाएं, ताकि कारागार आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली के साथ नई पहचान हासिल कर सकें।

अधिक उम्र के कैदियों और गंभीर बीमार बंदियों की सूची बनेगी

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश

दिया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के बंदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त कैदियों, छोटे बच्चों के साथ जेल में रह रहीं महिला बंदियों और जमानत राशि जमा न कर पाने के कारण बंद कैदियों की सूची तैयार की जाए। इन मामलों में मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि 2017 में प्रदेश की 70 जेलों की क्षमता 58,400 थी, जबकि 96,383 बंदी निरुद्ध थे। उस समय ओवरक्राउडिंग दर 1.77 थी, जो अब घटकर 1.03 हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 77 कारागार संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 77,673 है और इनमें 79,782 बंदी हैं। सात नए कारागार शुरू होने से 10,495 बंदियों की अतिरिक्त क्षमता विकसित हुई है। अमेठी, महोबा, हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर और हापुड़ में छह नए जेल निमार्णाधीन हैं।

जीएसटी रिफंड, अपील और पंजीयन में अनावश्यक देरी खत्म करने के निर्देश

राज्य कर विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कर प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिले, अपील निस्तारण और रिफंड जैसी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी समाप्त होनी चाहिए।

सीएम ने कहा कि तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर टैक्स चोरी रोकने के साथ-साथ वैध व्यापार को प्रोत्साहन देना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को व्यापारियों से लगातार संवाद बनाए रखने और फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।

यूपी जीएसटी कलेक्शन में देश में दूसरे स्थान पर

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि यूपी में रिफंड के मामले औसतन 27 दिन में निस्तारित हो रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 48 दिन है। फर्जी फर्मों और कर चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। एसआईटी गठन के बाद 180 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किए गए और सुनवाई के जरिए 2250 करोड़ रुपये की मांग सृजित हुई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को जीएसटी और वैट मद में कुल 1,15,977 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो संशोधित अनुमान का 98.8 प्रतिशत रहा। जीएसटी संग्रह में यूपी महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे स्थान पर रहा। फिलहाल 20,697 अपीलें विचाराधीन हैं।

जून से ब्लॉक स्तर पर चौपाल और किसान मेले

कृषि विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को समय-समय पर तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाए। जून से सभी ब्लॉकों में चौपाल आयोजित करने और इसके साथ किसान मेले लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से मिले और उन्हें आधुनिक व प्रगतिशील खेती से जोड़ा जाए।

उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, मंडियों और वेयरहाउस के आसपास साफ-सफाई और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

18-20 जिले सूखे के लिहाज से संवेदनशील

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के करीब 18 से 20 जिले सूखे की दृष्टि से संवेदनशील हैं। धान और मूंगफली की करीब 10 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित होने की आशंका है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने दलहन, तिलहन और श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

सीएम ने पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र किसानों को समय पर लाभ मिले और बीमा दावों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। किसानों को अब तक 99,032 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता वितरित की जा चुकी है।

पीएम पर भ्रामक वीडियो शेयर करने वाली लेखिका को गिरफ्तारी का डर, हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत

लेखिका मधु पूर्णिमा किश्वर ने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े भ्रामक वीडियो मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

(जीएनएस)।

चंडीगढ़। चर्चित लेखिका मधु पूर्णिमा किश्वर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जुड़ा कथित भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर करने के मामले में अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह बुधवार सुबह तक इस केस की स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे। मामला चंडीगढ़ के सेक्टर-26 पुलिस थाने में 19 अप्रैल को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।

आरोप है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संबंधित एक कथित भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो साझा किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मधु पूर्णिमा किश्वर को आरोपी बनाया है।

इससे पहले चंडीगढ़ की जिला अदालत ने 6 मई को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिला अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में मधु किश्वर ने कहा है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप अस्पष्ट और अस्थिर हैं। याचिका में दलील दी गई है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सामग्री नहीं रखी गई, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने जानबूझकर कोई आपराधिक कृत्य किया हो।

याचिका में यह भी कहा गया है कि विवादित वीडियो क्लिप न तो उन्होंने बनाई और न ही मूल रूप से अपलोड की। उनके अनुसार यह सामग्री किसी संदिग्ध और गैर-पहचाने इंटरनेट मीडिया हैंडल से पहले पोस्ट की गई थी।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने स्वयं सार्वजनिक तौर पर यह आशंका व्यक्त की थी कि संबंधित वीडियो संभवतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक की मदद से तैयार किया गया भ्रामक कंटेंट हो सकता है।

मधु किश्वर ने अपनी याचिका में यह तर्क भी रखा है कि एफआईआर में स्वयं यह उल्लेख किया गया है कि वीडियो मूल रूप से 'परदीप कौर ढिल्लों' नामक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया गया था।

शिकायत में कई अन्य इंटरनेट मीडिया लिंक और व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख है, लेकिन इसके बावजूद केवल उन्हें ही आरोपी बनाकर नामजद किया गया। याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसियों ने मामले में चयनात्मक कार्रवाई की है और केवल एक व्यक्ति को निशाना बनाया गया है। ऐसे में गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जानी चाहिए।

यूपी में बड़ा हादसा: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, दरोगा समेत सात की मौत, 24 यात्री घायल, सीएम ने जताया शोक

उत्तर प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है।

(जीएनएस)।

उन्नाव जिले में दिल्ली से गोरखपुर जा रही प्राइवेट स्लीपर बस मंगलवार सुबह पांच बजे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक दरोगा समेत सात यात्रियों की मौत हो गई। वहीं, तीन पुलिसकर्मी समेत 24 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के वक्त बस में 52 यात्री थे। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलटने के बाद100 मीटर तक घिसती चली गई।

दिल्ली से गोरखपुर जा रही स्लीपर बस में कुल 52 यात्री सवार थे। तेज रफ्तार होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और बस पुलिया से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। करीब आधे घंटे बाद यूपीडा कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

24 घायल लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर

घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 24 घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। एसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि कुछ घयल यात्रियों की हालत गंभीर होने से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

सीएम योगी ने जताया शोक

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने हादसे में हुईं मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा है। कहा कि मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

मृतकों में ये हैं शामिल

शिवचरन राम, उप निरीक्षक, बिहार सीवान पुलिस।

सुरेश कुमार जायसवाल पुत्र राम आधार जायसवाल, निवासी मुंडेरा बाजार चौरा चौरा, गोरखपुर।

विदेशी गुप्ता पुत्र मिश्रीलाल गुप्ता, निवासी मधुपुर थाना पीपीगंज, गोरखपुर।

विजय कुमार पुत्र रामजीत, निवासी गोविंदपुर थाना कप्तानगंज, बस्ती।

एक अज्ञात बंदी।

एक महिला व अन्य अज्ञात यात्री।

हादसे में ये हुए हैं घायल

हादसे के घायलों में गया, बिहार के वसीम (33) पुत्र शमसुद्दीन और देवरिया के गोलू (22) पुत्र धर्मेंद्र के साथ ही जहानाबाद, बिहार के रोहन (29) पुत्र सुरेन शामिल हैं। गोरखपुर क्षेत्र से जुड़े लोगों में बिसरोली के विनय पुत्र मुनिरका, कुसुमल बनी के अरुण कुमार (28), खदानी के सुरेंद्र कुमार (33) और अमरदीप (30) पुत्र प्रयाग गुप्ता शामिल हैं। इनके अलावा, शिकारपुर, बिहार के फरमान अंसारी (30) पुत्र मिखिल अंसारी, पीपरपाड़ी के शाहिद अख्तर पुत्र लाल मोहम्मद, बस्ती के सोम अली (28) पुत्र इंसान अली, दिल्ली के श्याम बिहार निवासी धनंजय (34) पुत्र बच्चन प्रसाद और बस्ती के ही विष्णु (25) पुत्र गंगाराम भी घायल हुए हैं। गोरखपुर के अन्य निवासियों में अरविंद (20) पुत्र शशिधर, राहुल (19) पुत्र त्रिलोकी और लेरब आलम (30) पुत्र मंजूर आलम शामिल हैं। साथ ही, महाराजगंज के टिकरा सुहागकुली निवासी धीरज (35), कुशीनगर के गणेश दीक्षित (19) पुत्र अशोक दीक्षित, कप्तानगंज (बस्ती) के आर्यन गुप्ता (12) पुत्र रामकुमार, गोरखपुर के परमजीत सिंह (28) पुत्र जितेंद्र यादव और उनकी पत्नी श्वेता यादव (25) भी शामिल हैं।

'मेरी कॉपी कहां गई?' कौन हैं वेदांत श्रीवास्तव जिसके एक पोस्ट से मचा बवाल, बोर्ड को देनी पड़ी सफाई

(जीएनएस)।

दिल्ली , CBSE की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर देशभर में जारी विवाद के बीच दिल्ली का 12वीं का छात्र वेदांत श्रीवास्तव अचानक राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गया। एक साधारण री-इवैल्यूएशन अनुरोध से शुरू हुआ मामला सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बन गया कि उइरए को सार्वजनिक रूप से जवाब देना पड़ा और आखिरकार बोर्ड ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए छात्र से माफी भी मांगी।

हालांकि इस पूरे विवाद ने सिर्फ उइरए की मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के गंभीर पहलू को भी उजागर कर दिया।

वेदांत श्रीवास्तव दिल्ली के एक 17 वर्षीय छात्र हैं जिन्होंने इस साल CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी। रिजल्ट आने के बाद उन्हें फिजिक्स विषय में उम्मीद से काफी कम अंक मिले। इसके बाद उन्होंने 19 मई को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी देखने के लिए आवेदन किया।

23 मई को जब CBSE की ओर से स्कैन कॉपी उपलब्ध कराई गई, तब वेदांत ने देखा कि उनके रोल नंबर पर अपलोड की गई फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका उनकी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि कॉपी में लिखी हैंडराइटिंग उनकी बाकी उत्तर पुस्तिकाओं से पूरी तरह अलग थी। इसके बाद वेदांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी फिजिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की कॉपियों के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सवाल उठाया कि आखिर उनकी असली उत्तर पुस्तिका कहां गई।

उन्होंने पोस्ट में लिखा-मैंने पूरे साल मेहनत की, नींद छोड़ी, मानसिक शांति छोड़ी और अब मुझे यह भी नहीं

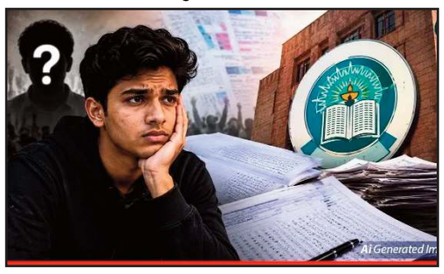

पता कि मेरी असली फिजिक्स कॉपी चेक हुई भी या नहीं।

हक की आवाज उठाने पर मिला 'पाकिस्तानी' और 'देशद्रोही' का टैग

वेदांत की पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई और लाखों लोगों तक पहुंच गई। लेकिन जहां एक तरफ कई लोग उनके समर्थन में आए, वहीं दूसरी ओर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और अभद्र टिप्पणियों का सामना भी करना पड़ा। कुछ यूजर्स ने उन पर उइरए की छवि खराब करने का आरोप लगाया। वहीं, उनके प्रोफाइल में लोकेशन South AsiÔ दिखने के कारण कई लोगों ने उन्हें पाकिस्तानी तक कह दिया। इस विवाद में दूरदर्शन न्यूज के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव का नाम भी सामने आया, जिन्होंने शुरूआत में वेदांत को पाकिस्तानी कहा था। बाद में उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा और उन्होंने माफी भी मांगी।

राहुल गांधी और CJP ने किया समर्थन

विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वेदांत के समर्थन में उतर आए। राहुल गांधी ने कहा कि एक 17 वर्षीय छात्र जिसने सिर्फ अपनी कॉपी में गड़बड़ी की शिकायत की, उसे एंटी-नेशनल और सोरॉस एजेंट कहा जाने लगा। वहीं सोशल मीडिया पर चर्चित Cockroach Janta Party (CJP) ने भी वेदांत का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी। पार्टी ने कहा कि छात्र ने सिर्फ CBSE की अव्यवस्था को उजागर किया है।

पिता और भाई का छलका दर्द

वेदांत के पिता संजय श्रीवास्तव ने बताया, "इस पूरी घटना ने मेरे बेटे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला है। कॉपियां बदलने के बाद से वह वैसे ही सो नहीं पा रहा था, ऊपर से सोशल मीडिया पर उसे पाकिस्तानी कहा जाने लगा। वह अब फोन से पूरी तरह दूर है।"

वहीं वेदांत के भाई सिद्धांत ने स्पष्ट किया कि वेदांत का पहले से कोई ट्विटर अकाउंट नहीं था, वह केवल पढ़ाई करता था। यह अकाउंट केवल इस गंभीर समस्या को उठाने के लिए तुरंत बनाया गया था, और तकनीकी सेटिंग की वजह से वहां साउथ एशिया रिफलेक्ट हो रहा था।

बैकफुट पर CBSE: गलती मानी, ईमेल से भेजी सही कॉपी

सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद उइरए ने मामले की जांच की और माना कि वेदांत के रोल नंबर पर गलत उत्तर पुस्तिका अपलोड हो गई थी। बोर्ड ने छात्र को ईमेल के जरिए सही उत्तर पुस्तिका भेजी और कहा कि उसके अंकों को अपडेट किया जाएगा। CBSE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि गलती हुई है, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर दूसरी कॉपी वेदांत के रोल नंबर से कैसे लिंक हो गई। बाद में वेदांत ने खुद पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें उनकी सही कॉपी मिल गई है और उनकी शिकायत सही साबित हुई।

क्या है OSM सिस्टम और क्यों उठ रहे सवाल?

उइरए ने इस साल पहली बार कक्षा 12वीं की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए Onf-Screen Marking (OSM) सिस्टम लागू किया था। इस प्रणाली में उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाता है और शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर ही मूल्यांकन करते हैं।

बोर्ड का दावा था कि इससे पारदर्शिता और तेजी आएगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों ने गलत स्कैन, धुंधली कॉपी, गायब पेज और गलत उत्तर पुस्तिका अपलोड होने जैसी शिकायतें कीं। वेदांत श्रीवास्तव का मामला सामने आने के बाद इस पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब छात्र और अभिभावक उइरए से अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद मूल्यांकन प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं।

रिटायर्ड जज सास गिरीबाला सिंहने सीबीआई की पूछताछ में क्या-क्या उगला? क्राइम सीन का जायजा

(जीएनएस)।

भोपाल में मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब CBI जांच के केंद्र में है। दिसंबर 2025 में हुई शादी के महज पांच महीने बाद 12 मई 2026 को कटारा हिल्स स्थित ससुराल में 33 वर्षीय ट्विशा को फंदे से लटका पाया गया। परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते उनकी हत्या की गई। पति समर्थ सिंह और सास, रिटायर्ड एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज गिरीबाला सिंह मुख्य आरोपी हैं।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच अपने हाथ में ली है। एजेंसी ने सोमवार (25 मई) को नई FIR दर्ज की, जिसमें समर्थ और गिरीबाला दोनों को नामजद किया गया। अब CBI टीम सक्रिय हो गई है और 26 मई को गिरीबाला सिंह के घर (क्राइम सीन) पर पहुंचकर बारीकी से जायजा लिया। आइए विस्तार से जानें CBI ने क्या क्या सवाल किए?

CBI की टीम गिरीबाला सिंह के भोपाल स्थित आवास पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक, टीम करीब 30 मिनट तक घर के अंदर रही। तीन गाड़ियों में आए छह सदस्यों की टीम में दो महिला अधिकारी भी शामिल थीं। लोकल पुलिस भी साथ थी।

नोएडा की मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की शादी भोपाल के समर्थ सिंह से दिसंबर 2025 को हुई थी। (परिवार के साथ ट्विशा)

टीम ने घर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया:

ट्विशा का कमरा कहां था?

घटना वाली रात समर्थ सिंह कहां सो रहे थे?

गिरीबाला सिंह उस समय कहां थीं?

ट्विशा को नीचे कैसे लाया गया?

फंदा कहां से लगा था?

टीम ने क्राइम सीन से जुड़े सबूत जुटाए, मौके पर मौजूद लोगों से प्रारंभिक जानकारी ली। घर से निकलते समय CBI अधिकारियों ने मीडिया से कोई बात नहीं की। यह CBI की जांच का पहला दिन था, इसलिए पूछताछ अभी प्रारंभिक स्तर की रही। आगे कड़ी पूछताछ होने की संभावना है।

सूत्रों का कहना है कि CBI फोन कॉल्स, घटना के ठीक पहले और बाद की गतिविधियों, और सबूतों की स्थिति पर फोकस कर रही है।

गिरीबाला सिंह पर क्या आरोप?

रसूख का दुरुपयोगः परिवार का आरोप है कि गिरीबाला सिंह (रिटायर्ड जज) ने जांच प्रभावित करने के लिए जजों, अधिकारियों और CCTV टेक्निशियन को फोन किए। मौत के तुरंत बाद उन्होंने कई कॉल्स किए, लेकिन पुलिस को सूचित करने में देरी हुई।

सबूतों से छेड़छाड़: CCTV फुटेज, वीडियो क्लिप्स रखने और मीडिया में बयान देने के आरोप।

सहयोग न करनेः राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि गिरीबाला जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं।

दहेज मांगः FIR में आरोप कि विदाई के समय ₹2 लाख की मांग की गई। शादी के बाद लगातार दहेज और पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद चलता रहा।

गिरीबाला सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने ट्विशा की मानसिक स्थिति और कथित ड्रग इश्यूज का जिक्र किया, जिसे पीड़ित पक्ष जांच भटकाने की कोशिश बता रहा है।

घटना की टाइमलाइन समझें...

9:41 PM: ट्विशा ने अपनी मां से फोन पर बात की। बैकग्राउंड में समर्थ सिंह की चीखें सुनी गईं। फोन अचानक कट गया।

इसके बाद गिरीबाला सिंह ने फोन उठाया और कहा कि वो अब दुनिया में नहीं रही और कॉल काट दी।

10:20 PM: समर्थ सिंह ट्विशा को AIIMS भोपाल ले गए। रात 12:05 AM को मृत घोषित किया गया।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

नेतन्याहू ट्रंप से हुए नाराज

अमेरिका-इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी, लेकिन अब इस जंग को रोकने के लिए दोनों देश आपस में सहमत नहीं हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू में भारी मतभेद सामने आ रहे हैं।

नेतन्याहू एक बार फिर से ईरान पर हवाई हमले शुरू करना चाहते हैं, वहीं ट्रंप हथियार से पहले वूटनीति के जरिए मामले को शांत करना चाह रहे हैं और अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकालने के लिए ईरान से कोई डील करने के चक्कर में हैं। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच लगभग एक घंटे तक बातचीत हुई। लेकिन दोनों एक मत नहीं हो पाए।

नेतन्याहू का कहना था कि ईरान की सैन्य क्षमता जब तक पूरी तरह बर्बाद न हो जाए, उनके यूरेनियम पर कब्जा न हो जाए हमले जारी रहने चाहिए।

राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि मध्यस्थ कतर और पाकिस्तान एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं ताकि युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म किया जा सके। इस पर दस्तखत होने के बाद 30 दिनों की बातचीत का दौर शुरू होगा। नेतन्याहू ट्रंप की नीति से सहमत नहीं थे। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान युद्ध रुकेगा और क्या नेतन्याहू अकेले ही ईरान युद्ध को आगे बढ़ाएंगे या फिर ट्रंप की चलेगी।

संसद में ही अपनों ने घेरा ट्रंप को

ने घेरा ट्रंप को अमेरिका की कांग्रेस (संसद) ने ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना व देश को हुए भारी नुकसान पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि लड़ाई के दौरान 42 अमेरिकी विमान नष्ट हुए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसी खबरें पहले भी मीडिया में आई थी पर ट्रंप प्रशासन ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की थी। यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) ने संकलित की है और यह अमेरिकी कांग्रेस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सीआरएस किसी भी राजनीतिक दल से संबंध की परवाह किए बिना अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को नीतिगत मुद्दों पर विश्लेषण मुहैया करता है। रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन, सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) और समाचार लेखों का हवाला दिया गया है। जिनके अनुसार क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए विमानों में मानवरहित हवाई वाहन, लड़ावू जेट और ड्रोन शामिल थे।

ईरान से युद्ध अमेरिका के लिए काफी भारी पड़ रहा है। विश्लेषकों का दावा है कि इस युद्ध में अमेरिका ने एक लाख करोड़ (एक ट्रिलियन) डॉलर के करीब पूंक चुका है। हालांकि सरकार ने इसे काफी कम करके दिखाया है। पेंटागन के एक वरिष्ठ बजट अधिकारी ने संसद को बताया कि युद्ध में अमेरिका को अब तक 29 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जबकि बजट 25 अरब डॉलर का था। ईरान युद्ध के कारण भारी खर्च और हथियार भंडार में आई कमी के मुद्दे पर ट्रंप के विपक्ष के साथसाथ अपनी पार्टी के सांसदों के भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर ईरान ने अभी तक युद्ध में हुए नुकसान का विवरण जारी नहीं किया है और अब भी दावा करता है कि वह अमेरिका के खिलाफ युद्ध जारी रखने में सक्षम है। राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान युद्ध को लेकर घर के अंदर ही बुरी तरह घिरते जा रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिकी जनता सड़कों पर उतर रही है वहीं अमेरिकी सेना और संसद सभी जगह ट्रंप को अपने ही उन्हें घेर रहे हैं।

क्या है अब्राहम एकॉर्ड? जिस पर बंटे सभी मुस्लिम देश, इजराइल को फायदा-पाक को क्या नुकसान?

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने एक बार फिर अब्राहम एकॉर्ड्स (Abraham Accords) को और आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ट्रंप ने कई मुस्लिम और अरब देशों से इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने की अपील की है। उनका कहना है कि यह कदम ईरान के साथ चल रही बातचीत और पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने के बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है।

ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किये, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों से अमेरिकी समर्थन वाले इस ढांचे में शामिल होने को कहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कोई देश इस पहल का समर्थन नहीं करता, तो उसका असर अमेरिका के साथ भविष्य के रिश्तों पर पड़ सकता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि अब्राहम एकॉर्ड आखिर है क्या?

Abraham Accords पर पाकिस्तान की राय

ट्रंप की इस नई पहल के बाद Abraham Accords फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब गाजा युद्ध, ईरान के साथ तनाव और फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर पूरा वेस्ट एशिया बंटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है।

आखिर क्या हैं Abraham Accords?

Abraham Accords अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में शुरू किए गए समझौतों का एक समूह है। इनका मकसद इजरायल और अरब देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को सामान्य बनाना था।

जिसमें पहला समझौता 15 सितंबर 2020 को इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन के बीच साइन हुआ था। बाद में मोरक्को और सूडान भी इसमें शामिल हो गए। वहीं कजाकिस्तान ने 2025 में औपचारिक रूप से इस समूह में एंट्री की, हालांकि उसके इजरायल के साथ रिश्ते पहले से मौजूद थे। यह समझौता यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म की साझा अब्राहमिक जड़ों के नाम पर रखा गया था और इसे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटनाओं में से एक माना जाता है।

फिलिस्तीन मुद्दे से हटे अरब देश

पहले ज्यादातर अरब देश इजरायल को मान्यता देने को फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान से जोड़ते थे। लेकिन Abraham Accords के बाद फोकस व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर शिफ्ट होने लगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ईरान का बढ़ता प्रभाव माना जाता है। इन समझौतों को 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन द्वारा इजरायल को मान्यता देने के बाद सबसे बड़ी अरब-इजरायल कूटनीतिक सफलता माना गया।

कौन-कौन हैं वर्तमान सदस्य?

फिलहाल Abraham Accords में इजरायल, UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान शामिल हैं। ट्रंप का दावा है कि इन समझौतों की वजह से इन देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास तेजी से हुआ है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा, Abraham Accords

सभी देशों के लिए शानदार साबित हुए हैं और भविष्य में मिडिल ईस्ट में असली ताकत और शांति लाएंगे।

ईरान डील के साथ जोड़ रहे हैं ट्रंप

ट्रंप का नया प्लान अमेरिका और ईरान के बीच चल रही संभावित शांति वाताओं से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत 'अच्छी तरह आगे बढ़ रही है'। ट्रंप ने कहा, 'यह सभी के लिए शानदार डील होगी, नहीं तो कोई डील नहीं होगी।' उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो क्षेत्र फिर से युद्ध और हिंसा की ओर लौट सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ किसी समझौते के तुरंत बाद सऊदी अरब, कतर और दूसरे मुस्लिम देश Abraham Accords में शामिल हो जाएं।

ट्रंप ने किन नेताओं से की बातचीत?

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर कई बड़े नेताओं से बातचीत की है। इनमें सऊदी क्राउन प्रिंस Mohammed bin Salman, UAE के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan, कतर के अमीर Tamim bin Hamad Al Thani, पाकिस्तान के सेना प्रमुख Asim Munir, तुर्किये के राष्ट्रपति Recep Tayyip Erdoğan, मिस्र के राष्ट्रपति Abdel Fattah el-Sisi और जॉर्डन के किंग Abdullah II of Jordan शामिल हैं।

पाकिस्तान ने सबसे पहले किया साफ इनकार

ट्रंप द्वारा संपर्क किए गए देशों में पाकिस्तान पहला ऐसा देश बना जिसने सार्वजनिक रूप से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री Khawaja Muhammad Asif ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे किसी समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसकी 'मूल विचारधारा' के खिलाफ हो। पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि जब तक 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनता, तब तक वह इजरायल को मान्यता नहीं देगा।

घरेलू राजनीति और खाड़ी देशों का दबाव

पाकिस्तान इस मुद्दे पर दो तरह के दबावों का सामना कर रहा है। एक तरफ वह आर्थिक मदद, प्रेषण और सुरक्षा सहयोग के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर धार्मिक समूह इजरायल के साथ संबंधों का लगातार विरोध करते हैं। 2020 में तत्कालीन प्रधानमंत्री Imran Khan ने भी Abraham Accords को खारिज कर दिया था। वहीं 2025 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री Ishaq Dar ने साफ कहा था कि फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान तक पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देगा।

मिडिल ईस्टी नेता भी दिखे असहज

रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में सऊदी अरब, वअए, कतर, पाकिस्तान, तुर्किये, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में यह मुद्दा उठाया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष खत्म होने के बाद जिन देशों ने अभी तक इजरायल को मान्यता नहीं दी है, उन्हें Abraham Accords के तहत आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस प्रस्ताव के बाद कॉल में कुछ समय के लिए चुप्पी छा गई थी। खासकर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा उत्साह नहीं दिखा।

गाजा युद्ध और फिलिस्तीन मुद्दा बना सबसे बड़ा रोड़ा

विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा युद्ध, ईरान के साथ तनाव और फिलिस्तीन को लेकर अरब दुनिया में गुस्से की वजह से अब्राहम एकॉर्ड्स का विस्तार आसान नहीं होगा। ईरान ने भी इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने कहा था, 'ईरान कभी भी ऐसे कब्जे वाले शासन को मान्यता नहीं देगा जिसने नरसंहार किया हो और बच्चों की हत्या की हो।'

फिलहाल प्रतिबंधों में ढील, यूरेनियम भंडार और ईरानी संपत्तियों जैसे मुद्दों पर बातचीत अभी भी अटकी हुई है। ऐसे में ईरान समझौते और Abraham Accords दोनों का भविष्य अभी अनिश्चित नजर आ रहा है।

अरुण कुमार : आईआईटी से ली डिग्री फिर 'मुखिया दीदी' के पति ने क्यों छोड़ी 12 साल पहले आईएएस रैंक की नौकरी?

(जीएनएस)।

दिल्ली की चमक-दमक, बड़ा सरकारी बंगला, ऊंचा अफसर वाला रुतबा और आराम से भरी जिंदगी... सब कुछ होते हुए भी एक शख्स ने गांव की टूटी सड़कों, बदहाल स्कूलों और संघर्ष भरी जिंदगी को चुन लिया। वजह सिर्फ एक थी, पत्नी का सपना। बिहार की चर्चित नेता रितु जायसवाल इन दिनों बीजेपी में शामिल होने को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन उनकी कहानी के पीछे एक ऐसा चेहरा भी है जिसकी चर्चा कम होती है।

यह कहानी है उनके पति अरुण कुमार की। उन्होंने IIT से पढ़ाई करने के बाद सिविल सर्विसेज की परीक्षा के

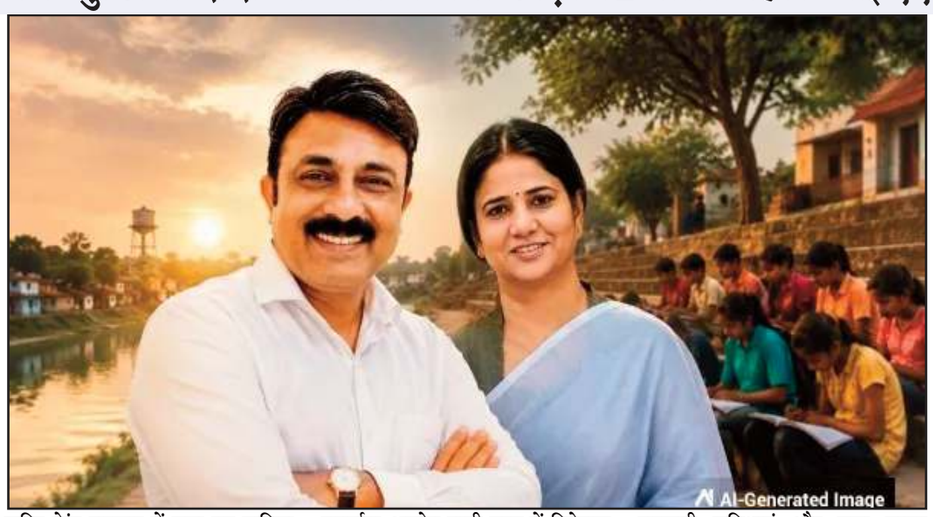

जरिए केंद्र सरकार में बड़ा पद हासिल किया, लेकिन बाद में पत्नी के सामाजिक मिशन के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। कभी दिल्ली के बड़े दफ्तरों में बैठकर फैसले लेने वाले अरुण कुमार आज गांव के बच्चों को घाट की सीढ़ियों पर बैठकर मुफ्त में पढ़ाते नजर आते हैं। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती।

अरुण कुमार पढ़ाई में शुरू से ही बेहद होनहार रहे। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और केंद्र सरकार के केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी उश्उ में निदेशक स्तर की जिम्मेदारी संभाली।

उश्उ का काम सरकारी विभागों और संस्थानों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की निगरानी करना और पारदर्शिता बनाए रखना होता है। निदेशक का पद केंद्र सरकार में काफी सीनियर माना जाता है, जहां बड़े प्रशासनिक फैसलों और जांच प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। इस पद पर अक्सर कअर, कढ़र और दूसरी वरिष्ठ सेवाओं के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। यही वजह है कि इसे आम भाषा में "कअर स्तर" की नौकरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊंची प्रशासनिक जिम्मेदारी, सरकारी सुविधाएं और बड़ा रुतबा मिलता है।

दिल्ली में उनका जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित था। सरकारी बंगला, गाड़ियां, स्टाफ और प्रशासनिक ताकत, सब कुछ उनके पास था। एक सफल अफसर के तौर पर उनकी पहचान बन चुकी थी और करियर भी शानदार चल रहा था।

पत्नी गांव गईं, तो बदल गया सोचने का तरीका

साल 2016 में रितु जायसवाल सीतामढ़ी जिले की सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया चुनी गईं। पंचायत बेहद पिछड़ी मानी जाती थी। गांव में बुनियादी सुविधाओं की हालत खराब थी। रितु ने तय किया कि वे गांव में रहकर बदलाव लाएंगी। उन्होंने दिल्ली की आरामदायक जिंदगी छोड़ दी और पंचायत में काम शुरू कर दिया।

इधर रितु गांव में संघर्ष कर रही थीं और उधर अरुण कुमार दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। धीरे-धीरे अरुण कुमार को महसूस हुआ कि सिर्फ दूर से समर्थन देने से काम नहीं चलेगा। पत्नी जिस मिशन के लिए लड़ रही हैं, उसमें साथ खड़ा होना जरूरी है।

12 साल की नौकरी बाकी थी, फिर भी दे दिया इस्तीफा

अरुण कुमार ने साल 2018 में ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से श्फ्र ले लिया, जबकि उनकी सेवा के करीब 12 साल बाकी थे। जिस नौकरी को पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, उसे छोड़कर वे गांव लौट आए। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने पंचायत के विकास में पूरी ताकत लगा दी। प्रशासनिक अनुभव का फायदा गांव को मिलने लगा और धीरे-धीरे सिंहवाहिनी पंचायत की तस्वीर बदलने लगी।

राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची पंचायत की पहचान

रितु जायसवाल और अरुण कुमार की मेहनत का असर कुछ ही सालों में दिखने लगा। पंचायत के विकास मॉडल की चर्चा बिहार से बाहर तक होने लगी। गांव में कई बदलाव हुए और सिंहवाहिनी पंचायत को मॉडल पंचायत के तौर पर पहचान मिलने लगी। इसी काम के लिए रितु जायसवाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बाद में जब रितु राज्य की राजनीति में ज्यादा सक्रिय हुईं, तब अरुण कुमार ने खुद पंचायत की कमान संभाल ली। साल 2021 के पंचायत चुनाव में वे मुखिया पद के लिए मैदान में उतरे और गांव वालों ने भारी वोट देकर उन्हें जीत दिलाई। लोगों ने इसे उनके त्याग और काम का सम्मान माना।

गंगा घाट पर चलती है गरीब बच्चों की क्लास

अरुण कुमार की पहचान सिर्फ मुखिया या पूर्व अधिकारी तक सीमित नहीं है। शिक्षा को लेकर उनका काम भी लोगों को काफी प्रभावित करता है। पटना के ठक्छ घाट पर गंगा किनारे उनकी खुली क्लास की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं। यहां वे गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। झुग्गी-झोपड़ी और कमजोर परिवारों के बच्चे घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गणित, विज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बिना फीस लिए बच्चों को पढ़ाने वाले अरुण कुमार का मानना है कि प्रतिभा सिर्फ बड़े शहरों या महंगे स्कूलों तक सीमित नहीं होती। सही मार्गदर्शन मिले तो छोटे गांवों के बच्चे भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।

प्लेऑफ से ठीक पहले बढ़ गई आरसीबी की मुश्किलें? कप्तान रजत पाटीदार के बयान से टेंशन में फैंस!

(जीएनएस)।

आईपीएल (2026) का पहला क्वालीफायर मुकाबला मंगलवार को धर्मशाला के एचपीसीए (HPCA) स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जाना है। इस हाई-स्टेक नॉकआउट मैच से ठीक पहले आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने आधुनिक टी-20 क्रिकेट के बदलते मिजाज और गेंदबाजों के बढ़ते दबाव को लेकर बड़ा बयान दिया है।

टी-20 क्रिकेट गेंदबाजों के लिए मुश्किल

रजत पाटीदार का मानना है कि मौजूदा दौर में बल्लेबाजों के मददगार पिचों और आधुनिक तकनीक के कारण खासकर तेज गेंदबाजों के लिए चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। आरसीबी के कप्तान ने बेबाकी से स्वीकार किया कि आईपीएल 2026 में गेंदबाजों के लिए स्थितियां बेहद कठिन रही हैं। उन्होंने इसके पीछे कई कारण बताए हैं।

बल्लेबाजों का रहा है बोलबाला

इस सीजन में पिचें पूरी तरह से बल्लेबाजों की मददगार रही हैं, जिससे रनों का अंबार लग रहा है। धर्मशाला जैसे मैदानों पर छोटी बाउंड्री और शाम के समय गिरने वाली ओस के कारण गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना और लाइन-लेंथ बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। पाटीदार के मुताबिक आधुनिक टी-20 क्रिकेट में अब गेंदबाजों के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। एक मामूली सी चूक भी तुरंत छह रनों में तब्दील हो जाती है।

'250 का स्कोर भी सेफ नहीं, आक्रामक क्रिकेट ही हमारा रास्ता'

रजत पाटीदार ने आधुनिक क्रिकेट की बदलती परिभाषा पर बात करते हुए कहा कि आईपीएल में अब 220 से लेकर 250 रन तक के स्कोर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। खेल इतनी तेजी से बदलता है कि किसी भी मोड़ पर मैच का पासा पलट सकता है। इसी वजह से उन्होंने साफ किया कि आरसीबी प्लेऑफ के दबाव में भी अपनी रणनीति नहीं बदलेगी। टीम अपनी पहचान बन चुके आक्रामक और अटैकिंग क्रिकेट को जारी रखेगी।

पाटीदार ने बताया क्या है टीम का प्लान?

पाटीदार ने कहा कि पावरप्ले

(शुरूआती 6 ओवर) में गेंदबाजी और लगातार विकेट चटकाना उनकी टीम की सबसे बड़ी ताकत रही है। वे इसी आक्रामक मानसिकता के साथ मैदान पर उतरेंगे। बेंगलुरु के कप्तान ने अपनी टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और रसिख सलाम ने इस पूरे सीजन में दबाव की परिस्थितियों में बेहतरीन गेंदबाजी की है और टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

इसके साथ ही उन्होंने चोट से उबर रहे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट पर बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि साल्ट अब पूरी तरह फिट हैं और नेट पर लगातार अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि, गुजरात के खिलाफ अंतिम एकादश (ढ'८ल्लॅ क) क्या होगी, इसका फैसला मैच से ठीक पहले परिस्थितियों को देखकर किया जाएगा। आईपीएल 2026 के फाइनल मैच को बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट किए जाने के विवादित फैसले पर जब पाटीदार से सवाल किया गया, तो उन्होंने एक सीनियर खिलाड़ी की तरह विवाद से बचते हुए कहा कि टीम का पूरा ध्यान इस समय वेन्यू पर नहीं, बल्कि क्वालीफायर-1 जीतकर सीधे फाइनल में जगह बनाने पर है।

अक्षरा सिंह ने सुनाई 'वेलकम टू द जंगल' के 'घिस घिस' की कहानी, कहा- अक्षय भोजपुरी लाइनों का मतलब पूछ रहे थे

(जीएनएस)।

अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के भोजपुरी गाने में अक्षरा सिंह अक्षय कुमार के साथ 'घिस घिस' गाने में डांस करती नजर आईं। उन्होंने कहा- मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अक्षय सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि अक्षय कुमार भोजपुरी भाषा को समझने में भी काफी रुचि दिखा रहे थे।

अक्षरा सिंह ने अक्षय संग काम करने पर कहा

भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के भोजपुरी गाने को लेकर चर्चा में हैं। इस गाने में वह अक्षय कुमार के साथ 'घिस घिस घिस' गाने में एनर्जेटिक अंदाज में नजर आईं। अक्षरा ने इस अनुभव को अपने करियर का बेहद खास पल बताया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा को इतने बड़े मंच पर पेश करना उनके लिए गर्व की बात है।

अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर गाने का क्लिप शेयर किया और उन्होंने लिखा, 'चेतावनी! ई गाना सुनके अगर आप नाचने लग जाएंङ्घत हमरा पर इल्जाम मत लगाइएगा। घिस घिस घिस रिलीज कर दिया गया है।' बता दें कि यह एक धमाकेदार पार्टी और डांस-

ओरिएंटेड आइटम नंबर है, जिसकी बीट्स बेहद शानदार है। इस गाने में बॉलीवुड के ग्लैमर और भोजपुरी का देसी अंदाज देखने को मिल रहा है। 'घिस घिस घिस' गाने में अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह जबरदस्त अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं। दोनों भोजपुरी स्टाइल को बखूबी से दशार्ते हुए ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। गाने को गायक विक्रम मोनट्रोज और सुप्रिया पाठक ने गाया है जबकि अभिनव शेखर ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और विक्रम मोनट्रोज ने ही इसे कंपोज भी किया है।

'कभी नहीं सोचा था कि मुझे अक्षय सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा'

आईएएनएस से बातचीत में अक्षरा सिंह ने कहा, 'मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अक्षय सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं अपनी भोजपुरी भाषा और संस्कृति को इतने बड़े स्तर पर पेश कर पाई।'

'अक्षय कुमार भोजपुरी भाषा को समझने की कोशिश कर रहे थे'

उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार ने उनका काफी सपोर्ट किया। सेट पर माहौल बेहद सहज था, जिससे वह खुलकर डांस और एक्सप्रेशन दे सकीं। अक्षरा ने कहा, 'अक्षय कुमार भोजपुरी भाषा को समझने में भी काफी रुचि दिखा रहे थे। उन्होंने भोजपुरी लाइन का उच्चारण और उसका मतलब भी पूछा। हालांकि, गाने की शूटिंग के समय अक्षय कुमार को तेज बुखार था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही गाना शुरू होता था, उनकी एनर्जी देखने लायक होती थी। स्टेप्स और एक्सप्रेशन को लेकर अक्षय कुमार का उत्साह काफी प्रेरणादायक रहा।'

अक्षरा बोलीं- गणेश आचार्य ने मुझे काफी सपोर्ट किया

अक्षय कुमार के साथ ही अक्षरा ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ काम करने का भी अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया, 'मैं बचपन से उनकी कोरियोग्राफी की फैन रही हैं। सेट पर गणेश आचार्य ने मुझे काफी सपोर्ट किया। जब मैं किसी शॉट को लेकर थोड़ा घबरा रही थी, तब गणेश आचार्य ने टीम से कहा कि अक्षरा यह शॉट आसानी से कर लेंगी। इतने बड़े एक्टर्स और टेक्नीशियंस से प्रोत्साहन मिलना किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। शूटिंग के दौरान मुझे एक्सप्रेशन, टाइमिंग और कैमरे के सामने प्रस्तुति की कई बारीकियां सीखने का मौका मिला।'

अक्षय कुमार का उनसे भोजपुरी लाइनें सीखना, खास पल

जब उनसे शूटिंग के सबसे यादगार पल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा अनुभव ही उनके लिए यादगार रहा। अक्षरा के मुताबिक, अक्षय कुमार का उनसे भोजपुरी लाइनें सीखना और गणेश आचार्य का उन्हें लगातार गाइड करना उनके लिए बेहद खास पल थे। बातचीत के दौरान अक्षरा सिंह ने बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह बिहार की बेटी हैं और चाहती हैं कि लोग भोजपुरी भाषा और संस्कृति को गर्व के साथ देखें। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता रहेगा।

जैकलीन कहती हैं- भोजपुरी तो हॉलीवुड से भी अच्छा है

अक्षय और अक्षरा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है। गाने में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार एक फ्लॉप भोजपुरी एक्टर के किरदार में हैं। उनकी तलाश करते हुए परेश रावल और जैकलीन फनार्डीज भी वहां पहुंचते हैं। गाने में अक्षय और अक्षरा को देखते हुए जैकलीन कहती हैं- भोजपुरी तो हॉलीवुड से भी अच्छा है।

आशीष चंचलानी ने कहा- मैंने इस वाले अक्षय कुमार को बहुत मिस किया

इस गाने का दर्शकों को काफी समय से बेसब्री से इंतजार था। रिलीज होते ही इसे फैंस की तरफ से बेहद प्यार मिल रहा है। साथ ही अक्षरा को भोजपुरी इंडस्ट्री के साथी कलाकार उन पर गर्व जता रहे हैं। एक्ट्रेस निधि झा लिखती हैं, 'हमें तुम पर गर्व है अक्षरा' तो एक्ट्रेस मोना सिंह ने लिखा, 'वाह। सुपर्ब एनर्जी, बधाई हो।' मोनालिसा ने कहा- वाह, क्या जबरदस्त एनर्जी है। वहीं आशीष चंचलानी ने कहा- मैंने इस वाले अक्षय कुमार को बहुत मिस किया। अक्षय की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी-एक्शन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून से सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हर मिनट महत्वपूर्ण! योगी सरकार ने एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम घटाने और अस्पतालों में दवा गुणवत्ता सुधारने के दिए निर्देश

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम कम करने, सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी दवाओं को हटाने और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। सरकार अब दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करेगी। बैठक में कोविड काल में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के समायोजन, आशा वर्करों के समय पर भुगतान, हेल्थ एटीएम सेवाओं के विस्तार और डिजिटल हेल्थ सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और तेज, भरोसेमंद और आम लोगों के लिए आसान बनाने पर योगी सरकार लगातार जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना या किसी भी इमरजेंसी में हर मिनट बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एम्बुलेंस सेवाओं को और तेज और प्रभावी बनाया जाए। साथ ही अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षित प्रसव व्यवस्था और गरीब मरीजों के इलाज को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए।

एम्बुलेंस सेवा को और तेज बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क हादसा हो, हार्ट अटैक हो या कोई अन्य गंभीर स्थिति, मरीज तक समय पर मदद पहुंचना सबसे जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 108 एम्बुलेंस सेवा और एडवांस लाइफ सपोर्ट (अछर) एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम और कम किया जाए ताकि मरीजों को जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सके।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस समय 375 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस संचालित हैं। अब तक 9.38 लाख से ज्यादा मरीजों को इन सेवाओं के जरिए रेफर किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस सेवाओं की निगरानी लगातार होनी चाहिए और संचालकों का भुगतान समय पर किया जाए, ताकि सेवाओं में कोई बाधा न आए।

एम्बुलेंस सेवा से जुड़े प्रमुख आंकड़े

सेवा आंकड़े

एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस 375

अब तक रेफर मरीज 9.38 लाख+

प्राथमिक लक्ष्य रिस्पॉन्स टाइम और कम करना

मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में तीन महीने से कम एक्सपायरी अवधि वाली दवाएं बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। उनकी जगह समय रहते नई दवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि मरीजों की सेहत से कोई समझौता न हो।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दवा वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए और मरीजों को समय पर सभी जरूरी दवाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और ग्रामीण इलाकों के लोग सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करते हैं, इसलिए वहां की व्यवस्था मजबूत होना बेहद जरूरी है।

आयुष इलाज भी होगा कैशलेस योजना में शामिल

योगी सरकार अब आयुष पद्धतियों को भी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पद्धतियों की आईपीडी सेवाओं को शामिल करने के निर्देश दिए।

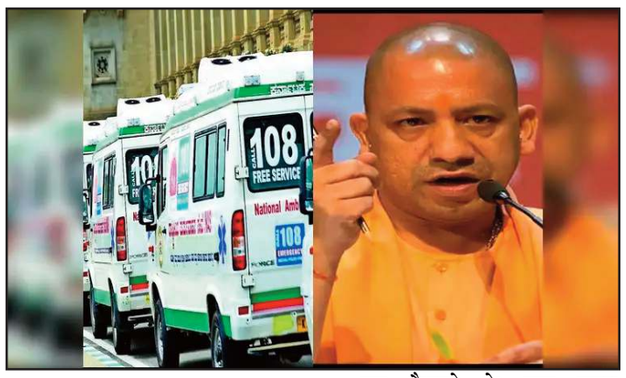

इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को आयुष पद्धति से इलाज कराने में भी कैशलेस सुविधा मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने से लोगों को इलाज के ज्यादा विकल्प मिलेंगे।

आयुष्मान योजना को बताया गरीबों का सबसे बड़ा सहारा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना आज गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों के क्लेम का भुगतान तय समय सीमा में किया जाए ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिलता रहे।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 6480 अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं और अब तक 96.75 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है।

आयुष्मान योजना के आंकड़े

सेवा आंकड़े

योजना से जुड़े अस्पताल 6480

मुफ्त इलाज पाने वाले मरीज 96.75 लाख+

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को और कम करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सुरक्षित और संस्थागत प्रसव व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर गर्भवती महिला तक समय पर जांच, इलाज और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचें। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और प्रसव के दौरान किसी भी लापरवाही से बचने पर भी जोर दिया गया।

कोविड काल के स्वास्थ्यकर्मियों के समायोजन की तैयारी

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का प्राथमिकता के आधार पर यथोचित समायोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि महामारी के समय इन स्वास्थ्यकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनके अनुभव का सही उपयोग होना चाहिए।

साथ ही उन्होंने आशा वर्करों के भुगतान में देरी न होने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे मजबूत कड़ी आशा वर्कर ही हैं, इसलिए उनका भुगतान समय पर होना जरूरी है।

डिजिटल हेल्थ और हेल्थ एटीएम सेवाओं का होगा विस्तार

बैठक में यह भी बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश में 15.28 करोड़ से ज्यादा अइलअ कऊ बनाई जा चुकी हैं। वहीं 15.14 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने हेल्थ एटीएम सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि गांवों और दूरदराज के इलाकों में भी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा आसानी से मिल सके।

टाटा टेक्नोलॉजीज और डेलॉयट के साथ योगी सरकार तैयार कर रही है युवाओं के लिए वैश्विक रोडमैप

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए युवाओं के कौशल विकास हेतु टाटा टेक्नोलॉजीज और डेलॉयट के साथ साझेदारी की है।

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के मोर्चे पर दो दिग्गज वैश्विक संस्थाओं को साथ जोड़ा है। प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिलाने और औद्योगिक प्रशिक्षण को 'इंडस्ट्री 4.0' के अनुरूप ढालने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज और डेलॉयट मिलकर एक भविष्यवादी रोडमैप तैयार कर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दोनों कंपनियों ने राज्य के युवाओं के कौशल विकास, आईटीआई संस्थानों के आधुनिकीकरण और वैश्विक रोजगार के अवसरों को लेकर अपनी विस्तृत प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया है।

ग्लोबल हब बनेंगे यूपी के आईटीआई

समीक्षा बैठक में टाटा टेक्नोलॉजीज के प्रतिनिधियों ने राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (कळक) के कायाकल्प की प्रगति रिपोर्ट साझा की। कंपनी पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल के तहत इन पारंपरिक संस्थानों को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'के रूप में अपग्रेड कर रही है।

इसके तहत युवाओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

एडवांस टेक्नोलॉजीः ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे उद्योगों की आधुनिक मांग के अनुसार प्रशिक्षण।

हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चरः संस्थानों में आधुनिक मशीनें और एडवांस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म स्थापित किए जा रहे हैं।

इंडस्ट्री-रेडी स्किल्सः युवाओं को इस तरह तैयार किया जा रहा है जिससे वे न केवल घरेलू उद्योगों बल्कि जर्मनी, जापान और खाड़ी देशों जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तकनीकी जरूरतों को पूरा कर सकें।

डेलॉयट का विजनः निवेश को सीधे रोजगार और स्किलिंग से जोड़ना

विश्व प्रसिद्ध परामर्शदाता कंपनी डेलॉयट के विशेषज्ञों ने 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में कौशल विकास की रणनीतिक भूमिका का खाका खींचा। डेलॉयट ने भविष्य के वैश्विक रोजगार रुझानों का विश्लेषण करते हुए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। राज्य में आने वाले बड़े औद्योगिक निवेश को सीधे स्थानीय युवाओं के कौशल प्रशिक्षण से लिंक किया जाए। उद्योगों की तात्कालिक मांग के अनुसार कस्टमाइज्ड स्किल कोर्स शुरू किए जाएं ताकि कंपनियों को निवेश करते ही कुशल श्रमशक्ति मिल सके। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तकनीक आधारित नए इनक्यूबेशन मॉडल विकसित किए जाएं।

हुनरमंद और आत्मनिर्भर युवा ही प्रदेश की ताकतः कपिल देव अग्रवाल

बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए इन वैश्विक संस्थाओं की तकनीकी विशेषज्ञता का पूरा लाभ उठाया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि दोनों संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाओं और सुझावों को बिना किसी देरी के जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल 'डिग्रीधारी' बनाना नहीं, बल्कि उन्हें 'सर्टिफाइड प्रोफेशनल' बनाना है।

पीपीपी मॉडल से मिलेगी कौशल विकास को नई दिशा

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि आने वाले समय में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए कौशल विकास कार्यक्रमों को और अधिक धारदार बनाया जाएगा।

शिक्षा को किताबी ज्ञान से निकालकर सीधे बाजार और रोजगार की मांग से जोड़ने का यह साझा प्रयास उत्तर प्रदेश को देश का सबसे मजबूत मानव संसाधन केंद्र (बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर असम से बंगाल तक तनाव, 8 बार चली गोलियां, क्यों हो रही झड़पें

(जीएनएस)।

भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक कई इलाकों में बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) के बीच झड़प की घटनाएं सामने आई हैं। पिछले करीब तीन हफ्तों से सीमा पर हालात सामान्य नहीं हैं।

अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार गतिविधियों को रोकने के दौरान दोनों देशों के सुरक्षा बल आमने-सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी ग्रामीणों की भूमिका भी कई घटनाओं में सामने आई है। बढ़ते तनाव के बीच BGB ने अब लोगों को जागरूक करने के लिए सीमा इलाकों में विशेष अभियान शुरू किया है।

सीमा पर क्यों बढ़ा तनाव?

भारत-बांग्लादेश सीमा पर 6 मई के बाद से तनाव काफी बढ़ गया है। खासतौर पर उन इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं जहां कंटीले तारों की बाड़ लगी हुई है। बीएसएफ लगातार अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती कर रही है। इसी दौरान कई बार बांग्लादेशी नागरिक और BGB जवान आमने-सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के बाद से गोलीबारी, धक्का-मुक्की और हिंसक झड़प जैसी आठ बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। सीमा के कई इलाकों में दोनों देशों के जवान हाई अलर्ट पर हैं।

BGB ने BSF पर क्या आरोप लगाए?

बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बीएसएफ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। BGB का दावा है कि 16 मई को ब्राह्मणबारिया के बिजोयनगर इलाके में इरऋने करीब 750 भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी क्षेत्र में भेजने की कोशिश की, जिसे रोक दिया गया। इसके अलावा सिलहट के सोनारहाट इलाके में गोलीबारी का आरोप भी लगाया गया। BGB का कहना है कि कई जगह 'जीरो पॉइंट' नियमों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि भारतीय पक्ष की तरफ से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित रही है।

सीमा गांवों में चला जागरूकता अभियान

तनाव बढ़ने के बाद BGB ने सीमा से लगे गांवों में विशेष अभियान शुरू किया है। ब्राह्मणबारिया इलाके में जवान मेगाफोन से लोगों को अवैध तरीके से सीमा पार नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं। BGB स्थानीय लोगों से तस्करी, मानव तस्करी और नशे के कारोबार से दूर रहने की अपील कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए आम लोगों का सहयोग जरूरी है। इस अभियान का मकसद ग्रामीणों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना है।

तस्करी और घुसपैठ भी बड़ी वजह

जानकारों का मानना है कि सीमा पर बढ़ते तनाव की बड़ी वजह सिर्फ बाड़ेबंदी नहीं है। अवैध घुसपैठ, पशु तस्करी, ड्रग्स और मानव तस्करी जैसे अपराध भी हालात बिगाड़ रहे हैं। कई बार सीमा पार करने वाले लोग सुरक्षा बलों के हथियार छीनने की कोशिश करते हैं, जिससे गोलीबारी की नौबत आ जाती है। सीमा के कई इलाकों में स्थानीय तस्कर गिरोह सक्रिय बताए जाते हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के सुरक्षा बल लगातार सख्ती बढ़ा रहे हैं।

योगी बोले- ढाई करोड़ की कार से चलने वाला नगर निगम का 45 रुपये का गमला चुराकर ले गया, ये चोरी का नया मॉडल

मुख्यमंत्री ने नगर निगम कार्यक्रम में सरकारी संपत्ति की चोरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि महंगी कारों से आने वाले लोग भी सार्वजनिक स्थानों से गमले चुरा रहे हैं। सीसीटीवी में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने इसे जनता के पैसे की बबार्दी बताते हुए नागरिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

(जीएनएस)।

लखनऊ, सीएम योगी ने लखनऊ नगर निगम के एक समारोह में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर तंज कसा। उन्होंने कहा, ढाई करोड़ की कार में चलने वाले नगर निगम का 45 रुपये का गमला चुराकर ले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे से इस तरह की चोरी की घटना देखी।

हम गमला लगाते हैं, तो कोई कार से आता है और गमला उठाकर ले जाता है। जितना कार का तेल लग रहा है, उतने में नया गमला ले सकते हो। ये चोरी का नया मॉडल है। अब हर जगह सीसीटीवी लगे हैं, हम उससे देखते रहते हैं। पता लगता है कि ढाई करोड़ की कार से 45 रुपए के गमले चुरा रहे हैं।

45 रुपए के गमले खरीदकर आप घर में लगा सकते थे। आपका सम्मान भी रहता और शहर भी अच्छा दिखता। एक बार तो मेरे मन में आया था कि गमला चोरी करने वालों की फोटो चौराहे पर लगवाऊं, क्योंकि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, वह जनता का है। यह न तो हमारा है, न वित्त मंत्री खन्नाजी का और न ही ऊर्जा मंत्री शमार्जी का।'

जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने पहली बार सभी 17 नगर निगमों में मेयर की सीट भाजपा की झोली में डालीं। सभी नगर निगमों में भाजपा का बोर्ड बना। इसका परिणाम रहा कि नगर निगम ने 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए, विकास व स्वच्छता का मॉडल दिया। हमें पिछली सरकारों के पापों के गड्ढों को भरने, भ्रष्टाचार के कूड़े को साफ करने में समय भी लगा। विकास पर खर्च होने वाला पैसा जनता का है। इसे मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं दे रहे,

बल्कि केवल उसका उचित नियोजन कर रहे हैं। जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा। यही पीएम मोदी जी का विजन है, प्रेरणा है।

स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी

सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में तीसरा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। यह केवल महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकें, गीला-सूखा कूड़ा अलग करें।

सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। नालियों में कूड़ा न फेंकें और सरकारी संपत्तियों का नुकसान भी न करें। लोग कहते हैं कि लखनऊ बहुत साफ-सुथरा है, जब सरकार की कार्यपद्धति साफ-सुथरी होती है तो ऐसा ही होता है।

मंत्री, महापौर, पार्षद, पूरी कार्यकारिणी, अधिकारी, सुपरवाइजर तथा सफाई कर्मचारी, सब जुटते हैं तो स्वच्छता दिखाई देती है। सीएम ने ढाई करोड़ की कार से आकर गमला चोरी करने वालों पर कटाक्ष किया और कहा कि सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 45 रुपये का गमला खरीद लेते तो सम्मान भी बना रहता और शहर भी सुंदर दिखता।

नकारात्मक राजनीति करने वालों को दिया जवाब

सीएम ने लखनऊ को प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर व नगर निगम बताते हुए कहा कि जितना बड़ा दायित्व होगा, उतनी बड़ी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन लखनऊ व प्रदेश चुनौतियों का बखूबी सामना कर रहा है।

सीएम ने नकारात्मक राजनीति करने और सकारात्मक पहल पर अंगुली उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि तीन वर्ष में नगर निगम, 9 वर्ष में प्रदेश और 12 वर्ष में पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के कार्यक्रम नए प्रतिमान से बढ़ाए गए।

नगर निकाय, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सरकार ने कुछ नया करके दिखाया है। हमारे शहर 'ईज ऑफ लिविंग'की दृष्टि से स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित हैं। लखनऊ नगर निगम ने गत वर्ष 200 करोड़ से अधिक का बांड जारी किया था, जबकि 2017 के पहले यहां के बांड की कीमत 25 करोड़ भी नहीं थी।

देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास अस्वस्थ मानसिकता

सीएम योगी ने कहा कि ऊर्जा संकट वैश्विक बन चुका है। अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण सप्लाई लाइन बाधित हुई है। दुनिया के तमाम क्षेत्रों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जिस अमेरिका के पास अपने ऊर्जा के क्षेत्र हैं, वहां पेट्रोलियम पदार्थ के दाम दोगुने से अधिक हुए हैं।

महंगाई चरम पर है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में लगातार इसे नियंत्रित किया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम दुनिया में बढ़ेंगे, सप्लाई चेन बाधित होगी तो उसका असर यहां भी पड़ेगा, लेकिन संकट के समय देश के साथ खड़े होने के बजाय देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास अस्वस्थ मानसिकता का पर्याय है।

जरूरत के अनुसार ही करें बिजली की खपत

सीएम योगी ने कहा कि गर्मी एकाएक बढ़ने से तमाम थर्मल पावर प्लांट ने अचानक शटडाउन ले लिया। उत्पादन पर असर पड़ा। 2017 तक यूपी में पीक पावर की सप्लाई 15-16 हजार मेगावाट रहती थी, आज यह 32-33 हजार मेगावाट पहुंच गई है।

उस समय 6 हजार मेगावाट उत्पादन था, जबकि आज 13 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। रिन्युवल एनर्जी का उत्पादन लगभग 10 हजार मेगावाट तक बढ़ा है, लेकिन हमारी आवश्यकता 33-35 हजार मेगावाट है। एलपीजी संकट को देखते हुए लोग खाना पकाने में इलेक्ट्रिक हीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की समस्या हर किसी की समस्या है। किसी के बहकावे में न आएं। जितनी आवश्यकता है, उतनी ही बिजली खपत करें।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड में निमार्णाधीन कुआं बना काल, मिट्टी खिसकने से मजदूरों की दर्दनाक मौत

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड से एक बेहद दुखद और हृदयविदारक खबर सामने आई है। यहां के ग्राम पंचायत बीहरपुरवा के नयापुरवा में मंगलवार को एक निमार्णाधीन कुएं की मिट्टी अचानक भरभराकर धंस गई। जिला जनसंपर्क कार्यालय (ढफ्ड खर ढअठठअ) द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मलबे के नीचे दबे 5 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। वहीं, राहत की बात यह रही कि 2 व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल की टीम तुरंत जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची थी। ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे इस निमार्णाधीन कुएं में जब मिट्टी धंसी, तो वहां काम कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। आनन-फानन में मलबे को हटाने और दबे हुए लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

घंटों चली कड़ी मशक्कत

घंटों चली कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 5 लोगों की सांसें थम चुकी थीं। इस भीषण हादसे के बाद से पूरे बीहरपुरवा और नयापुरवा क्षेत्र में कोहराम मच गया है और मृतकों के परिवारों में चीख-पुकार मची हुई है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

मजदूरों की आंखों के सामने खत्म हो गईं जिंदगी

स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, खेत में पिछले करीब 10 दिनों से 7 मजदूरों द्वारा इस कुएं की खुदाई का काम किया जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे खुदाई के दौरान दो मजदूर पानी पीने के लिए जैसे ही ऊपर आए, वैसे ही अचानक कुएं की मिट्टी भरभराकर धंस गई। उन दोनों की आंखों के सामने अंदर काम कर रहे उनके 5 साथी मलबे में समा गए।

5 मौतों के बीच 2 मासूम बच्चे भी मलबे में दबे

इस दर्दनाक हादसे का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि मलबे में 5 श्रमिकों के साथ दो बच्चे भी दब गए हैं। रेस्क्यू टीम द्वारा बच्चों को बाहर तो निकाल लिया गया है, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक और गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच कड़ा संघर्ष कर रहे हैं।

मिट्टी ने खड़े किए प्रशासन पर गंभीर सवाल

हादसे वाली जगह से आ रही तकनीकी जानकारियों के मुताबिक, जिस स्थान पर कुएं की खुदाई हो रही थी, वहां की मिट्टी बेहद भुसभुसी और कमजोर थी। ऐसी जगह पर बिना सुरक्षा मानकों के गहरी खुदाई करना सीधे तौर पर हादसे को न्योता देना था। अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर यह खुदाई किसी व्यक्तिगत काम के लिए थी या किसी

निकाय चुनाव में वोटिंग को लेकर केजरीवाल की अपील, बोले- 'आपका वोट असली ताकत'

(जीएनएस)।

पंजाब में जारी नगर निगम और निकाय चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। केजरीवाल ने लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है और यही वोट प्रदेश के विकास, स्थानीय समस्याओं के समाधान और परिवार की खुशहाली तय करता है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश जारी करते हुए कहा, मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि पंजाब में चल रहे निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपका वोट लोकतंत्र में आपकी ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों की छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान भी मतदान से चुनी गई सरकार और जनप्रतिनिधियों

के जरिए ही संभव होता है। ऐसे में हर नागरिक को मतदान प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।

पंजाब में कई सीटों पर जारी है मतदान

पंजाब के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही कई जिलों में पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। खासकर शहरी इलाकों में युवाओं और महिलाओं में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

AAP के लिए अहम माने जा रहे हैं चुनाव

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पंजाब के निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद यह पहला बड़ा स्थानीय चुनाव है, जहां पार्टी अपने जनाधार और संगठन की मजबूती को परख रही है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल भी इन चुनावों को प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं।